Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

15 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए IIM शिलांग में नॉर्थ-ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया।

11 जुलाई 2025 को, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), शिलांग, मेघालय में आयोजित "विचार से निगमन तक" विषय पर आधारित IICA नॉर्थ-ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया।

• कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MoCA) के तहत भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान (IICA) द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम ने पूर्वोत्तर उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए उद्यमियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों को एक साथ लाया।

• उद्घाटन सत्र में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी, मेघालय के मुख्य सचिव डोनाल्ड फिलिप्स वाहलांग और IICA के महानिदेशक एवं CEO ज्ञानेश्वर कुमार सिंह जैसे गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।

Key Points:-

(i) एक प्रमुख उपलब्धि उमसावली, शिलांग में IICA के पहले उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय परिसर की आधारशिला रखना था, जो इस क्षेत्र में कॉर्पोरेट प्रशासन, नीति शिक्षा और स्टार्ट-अप समर्थन के लिए एक स्थायी संस्थागत आधार स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

(ii) इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर भारत के 39 स्टार्ट-अप, किसान उत्पादक संगठनों, वित्तीय संस्थाओं और इनक्यूबेटरों ने भाग लिया। इसके अलावा, क्षमता निर्माण, अनुपालन प्रशिक्षण और इनक्यूबेटर संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए MATI, IIM शिलांग, STPI, ICAI, ICSI, ICMAI और NLU असम जैसे संगठनों के साथ सात समझौता ज्ञापनों (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए।

(iii) चार विषयों - स्टार्टअप निगमन और विनियामक ढांचे, इनक्यूबेशन मॉडल, फंडिंग तंत्र (seed-to-scale), और बाजार पहुंच रणनीतियों - के आसपास संरचित इस सम्मेलन में तकनीकी सत्र, फायरसाइड चैट और निवेशक पैनल शामिल थे, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय नवाचारों को स्केलेबल उद्यमों में बदलना था।

2. MoHI ने ग्रीन फ्रेट मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए PM E DRIVE के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए भारत की पहली प्रोत्साहन योजना शुरू की।

भारी उद्योग मंत्रालय (MoHI) ने हाल ही में PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) कार्यक्रम के तहत

इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए भारत की पहली समर्पित प्रोत्साहन योजना का अनावरण किया।

• 11 जुलाई 2025 को केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी द्वारा घोषित, यह पहल स्वच्छ मालवाहक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

• यह योजना केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (CMVR) के अनुसार N2 और N3 श्रेणियों में प्रत्येक इलेक्ट्रिक ट्रक पर ₹9.6 लाख तक की माँग प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है, जिससे उच्च अग्रिम लागत की भरपाई में मदद मिलती है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर 5,600 ई-ट्रक तैनात करना है, जिनमें से 1,100 वाहन दिल्ली में होंगे, और इसके लिए ₹100 करोड़ के समर्पित उप-आवंटन की व्यवस्था की गई है।

• विश्वसनीयता और दीर्घकालिक प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए, निर्माता-समर्थित वारंटी अनिवार्य हैं: बैटरी 5 वर्ष या 5 लाख किमी के लिए, और वाहन और मोटर 5 वर्ष या 2.5 लाख किमी के लिए, जो भी पहले हो। प्रोत्साहनों को अग्रिम मूल्य कटौती के रूप में दिया जाएगा और मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) को PM E-DRIVE पोर्टल के माध्यम से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

Key Points:-

(i) इस योजना में पुराने डीजल ट्रकों को हटाने का भी प्रावधान है, जिससे उत्सर्जन कम करने और लॉजिस्टिक्स बेड़े का आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी। प्राथमिकता के आधार पर इसकी तैनाती प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: सीमेंट, बंदरगाह, इस्पात और लॉजिस्टिक्स, जहाँ टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और वोल्वो आयशर जैसी प्रमुख ओईएम कंपनियाँ पहले से ही इलेक्ट्रिक ट्रकों की आपूर्ति कर रही हैं।

(ii) इस पहल के तहत, सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने दो वर्षों में 150 ई-ट्रक खरीदने और अपने किराए के बेड़े का 15% इलेक्ट्रिक सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। विश्लेषकों का मानना है कि इस योजना से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी, शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और बेड़े संचालकों के लिए स्वामित्व की कुल लागत (TCO) को कम करने के PM E-DRIVE के लक्ष्य को बल मिलेगा।

(iii) यह कदम PM E-DRIVE कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख नीतिगत बदलाव को दर्शाता है, जिसे सितंबर 2024 में मंत्रिमंडल द्वारा ₹10,900 करोड़ की राशि के साथ मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत विशेष रूप से इलेक्ट्रिक ट्रकों (e-trucks) के लिए ₹500 करोड़ का उप-आवंटन किया गया है, ताकि भारत के ग्रीन फ्रेट ट्रांजिशन को गति मिल सके और देश के 2070 तक नेट-ज़ीरो और 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

3. बिरला संस्थान आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI-केंद्रित परिसर शुरू करेगा।

भारत 2027 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में अपना पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) परिसर शुरू करने के लिए तैयार है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS) पिलानी अपने 1,219 करोड़ रुपये के "प्रोजेक्ट विस्तार" के हिस्से के रूप में इस पहल का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश

भर में AI-आधारित उच्च शिक्षा और अनुसंधान में क्रांति लाना है।

• BITS पिलानी आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का पहला AI+ परिसर स्थापित करेगा, जिसमें AI, मशीन लर्निंग (ML), डेटा साइंस और उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रमुख ध्यान दिया जाएगा।

• इस परियोजना में 1,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश शामिल है और इसमें दो चरणों में 3,000 से 7,000 छात्रों के अध्ययन की उम्मीद है, जो अत्याधुनिक शैक्षणिक और अनुसंधान बुनियादी ढांचे की पेशकश करेगा।

• नया परिसर BITS पिलानी की ₹1,219 करोड़ की बुनियादी ढाँचा विस्तार योजना, जिसे "प्रोजेक्ट विस्तार" नाम दिया गया है, का एक हिस्सा है, जिसमें पिलानी, गोवा और हैदराबाद स्थित इसके मौजूदा परिसरों का उन्नयन भी शामिल है। 2031 तक कुल छात्र क्षमता 18,500 से बढ़कर लगभग 26,000 हो जाएगी। उन्नयन में आधुनिक प्रयोगशालाएँ, डिजिटल कक्षाएँ और स्टार्टअप इनक्यूबेशन ज़ोन शामिल होंगे।

Key Points:-

(i) एक समानांतर घटनाक्रम में, आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में एक AI विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एनवीडिया कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है। जून 2025 में एक समझौता ज्ञापन (MOu) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत एनवीडिया अपने वैश्विक इंसेप्शन प्रोग्राम के माध्यम से 10,000 इंजीनियरिंग छात्रों को कौशल प्रदान करेगा और 500 AI स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान करेगा, जिससे भारत के AI स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।

(ii) यह दोहरी पहल अमरावती को गहन तकनीकी नवाचार के एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करती है, जो शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार को एक साथ लाती है। आंध्र प्रदेश सरकार और BITS पिलानी तथा एनवीडिया जैसे संस्थानों के रणनीतिक सहयोग से, भारत अपने विकसित भारत और डिजिटल इंडिया मिशनों को आगे बढ़ाने के लिए एक विश्वस्तरीय AI प्रतिभा और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है।

4. दिल्ली सरकार जुलाई 2025 से महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए 'सहेली स्मार्ट कार्ड' लॉन्च करेगी।

दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में एक बड़े उन्नयन के तहत, दिल्ली सरकार जुलाई 2025 में 'सहेली स्मार्ट कार्ड' लॉन्च करेगी। यह पहल मौजूदा गुलाबी टिकट प्रणाली की जगह लेगी, जिससे दिल्ली के सत्यापित निवासी महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी, साथ ही डिजिटल प्रमाणीकरण और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित होगा।

• 'सहेली स्मार्ट कार्ड' पहल, दिल्ली परिवहन निगम (DTC) द्वारा राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) के ढांचे के तहत कार्यान्वित की जा रही है। स्मार्ट कार्ड प्रणाली, मुफ़्त यात्रा योजना को डिजिटल बनाने का प्रयास करती है, जिसे दिल्ली सरकार ने 2019 में महिलाओं के लिए शुरू किया था और बाद में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी लागू किया।

• केवल 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिल्ली के वास्तविक निवासी ही सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए

आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदकों को निवास का वैध प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। पात्रता का सत्यापन "अपने ग्राहक को जानें" (KYC) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभों का दुरुपयोग न हो।

• सहेली स्मार्ट कार्ड अधिकृत बैंकों द्वारा जारी किया जाएगा और इसे DTC के स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (AFCS) के माध्यम से सक्रिय करना होगा। यह कार्ड टॉप-अप और रिचार्ज सुविधाओं का समर्थन करता है और न केवल डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए, बल्कि दिल्ली मेट्रो जैसी सशुल्क सेवाओं पर भी काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Key Points:-

(i) दो श्रेणियों के कार्ड उपलब्ध कराए जाएँगे: (i) गैर-KYC कार्ड, जो पते के प्रमाण के आधार पर जारी किए जाएँगे और DTC बसों और दिल्ली मेट्रो में इस्तेमाल किए जा सकेंगे; और (ii) KYC-अनुपालक कार्ड, जिनमें उपयोगकर्ता का नाम और तस्वीर शामिल होगी, जिससे विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों पर संपर्क रहित भुगतान संभव होगा। इससे मल्टीमॉडल स्मार्ट परिवहन पहुँच को बढ़ावा मिलेगा।

(ii) यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए समावेशी, कैशलेस और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के दिल्ली सरकार के व्यापक उद्देश्य का समर्थन करती है। यह स्मार्ट मोबिलिटी पहल और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के लक्ष्यों के अनुरूप भी है।

(iii) स्मार्ट कार्ड की शुरुआत से सार्वजनिक क्षेत्र में हाशिए पर पड़े समूहों की भागीदारी बढ़ने, मानवीय हस्तक्षेप कम होने और सब्सिडी वितरण में जवाबदेही आने की उम्मीद है। यह दिल्ली में चल रहे गतिशीलता सुधारों को और मज़बूत करेगा, जिनमें इलेक्ट्रिक बसें, केवल महिलाओं के लिए मार्शल और मोबाइल ऐप के ज़रिए बसों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग शामिल है।

5. दूरसंचार विभाग ने युवाओं को डिजिटल राजदूत के रूप में सशक्त बनाने के लिए देश भर में 'संचार मित्र योजना' शुरू की।

संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग (DoT) ने जुलाई 2025 में 'संचार मित्र योजना' शुरू की थी। इसका उद्देश्य छात्र स्वयंसेवकों को 'डिजिटल एंबेसडर' के रूप में नियुक्त करके नागरिकों में डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा का प्रसार करना है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य जनता और भारत के बढ़ते दूरसंचार एवं डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की खाई को पाटना है।

• संचार मित्र योजना का पहला आउटरीच सत्र असम लाइसेंस्ड सर्विस एरिया (LSA) द्वारा गुवाहाटी, असम स्थित BSNL भवन में आयोजित किया गया।

• इस सत्र की अध्यक्षता दूरसंचार विभाग के महानिदेशक (DG) कार्यालय की सलाहकार सुनीता चंदर ने की। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) सहित 18 प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों ने भाग लिया।

• संचार मित्र योजना के तीन मुख्य स्तंभ हैं: कनेक्ट, एजुकेट और इनोवेट, जिसका उद्देश्य एक सूचित, सुरक्षित और समावेशी दूरसंचार वातावरण बनाना

है। स्वयंसेवक नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र (EMF) विकिरण जागरूकता और ज़िम्मेदार मोबाइल उपयोग प्रथाओं के बारे में शिक्षित करेंगे, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।

Key Points:-

(i) शैक्षणिक संस्थान दूरसंचार, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों से छात्रों को नामांकित करेंगे। ये छात्र राष्ट्रीय संचार अकादमी-प्रौद्योगिकी (एनसीए-टी) और दूरसंचार विभाग के मीडिया विंग के विशेषज्ञों द्वारा विकसित प्रमाणित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण में 5G, 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और नैतिक दूरसंचार उपयोग शामिल हैं।

(ii) शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्र राजदूतों को इंटर्नशिप, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर, तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) मंचों और वैश्विक नवाचार मिशनों सहित प्रमुख राष्ट्रीय दूरसंचार परियोजनाओं में भागीदारी के लिए मान्यता प्राप्त होगी।

(iii) इस कार्यक्रम को शुरू में चुनिंदा संस्थानों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन जुलाई 2025 तक इसे आधिकारिक तौर पर भारत के सभी दूरसंचार सर्किलों में लॉन्च कर दिया गया है। इसका पर्यवेक्षण केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (गुना, मध्य प्रदेश) और संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी (गुंटूर, आंध्र प्रदेश), संचार मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

6. केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सीमा शुल्क बुनियादी ढांचे में वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया।

जुलाई 2025 में, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नई दिल्ली स्थित ICAR-NASC परिसर के सी. सुब्रमण्यम सभागार में व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। CBIC के अंतर्गत केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (CRCL) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य सीमा शुल्क अवसंरचना, व्यापार दक्षता और प्रयोगशाला आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है।

- **वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधीन कार्यरत केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (CRCL) द्वारा "निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता" विषय पर व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (NASC), पूसा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।**

- **केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें CBIC के सदस्य (कर नीति एवं विधि) विवेक रंजन और CBIC के सदस्य (सीमा शुल्क) सुरजीत भुजबल सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। यह सम्मेलन व्यापार-संबंधी प्रयोगशाला कार्यों के आधुनिकीकरण, प्रक्रियाओं के मानकीकरण और नियामक सहयोग को मज़बूत करने हेतु नीतिगत रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय मंच के रूप में कार्य किया।**

• इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परीक्षण में देरी को कम करके, प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे को उन्नत करके और अनुसंधान एवं विकास (R&D) क्षमताओं को बढ़ाकर भारत के व्यापार सुविधा तंत्र को मजबूत करना था। CRCL का लक्ष्य बंदरगाहों और प्रवेश बिंदुओं पर अपने प्रयोगशाला नेटवर्क का विस्तार करना और वैज्ञानिक एवं तकनीकी उत्कृष्टता के माध्यम से सीमा शुल्क दक्षता में सुधार करना भी है।

Key Points:-

(i) सम्मेलन में तकनीकी प्रशिक्षण और हितधारक सहयोग के माध्यम से कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर भी ज़ोर दिया गया। अंतर-संस्थागत समन्वय बढ़ाने, नमूनाकरण प्रक्रियाओं में सुधार लाने और पेट्रोलियम, रसायन एवं संबद्ध उत्पादों के लिए डेटा-आधारित व्यापार निदान को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष हितधारक कोर समूह का प्रस्ताव रखा गया।

(ii) सम्मेलन के एक भाग के रूप में, "सीमा पर विज्ञान: भारतीय सीमा शुल्क प्रयोगशालाओं की कहानी" शीर्षक से एक वृत्तचित्र का विमोचन किया गया, जिसमें 1912 में अपनी स्थापना के बाद से CRCL की यात्रा का विवरण दिया गया।

(iii) इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम तरल पदार्थों के नमूने लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर एक वीडियो के साथ-साथ CRCL कॉफी टेबल बुक और ब्रोशर भी जारी किया गया।

INTERNATIONAL

1. भारत ने सऊदी अरब के साथ 3.1 मिलियन टन DAP के लिए 5 साल की दीर्घकालिक उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

11-13 जुलाई 2025 तक रियाद और दम्मम की अपनी यात्रा के दौरान, रसायन और उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा ने सऊदी अरब की सरकारी स्वामित्व वाली खनन कंपनी मा'अदेन और भारतीय कंपनियों इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL), KRIBHCO, कोरोमंडल और कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के साथ ऐतिहासिक दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

• यह समझौता वित्तीय वर्ष 2025-26 से पांच वर्षों तक 3.1 मिलियन मीट्रिक टन डायमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरक की वार्षिक आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जिसमें पांच साल के विस्तार का विकल्प भी शामिल है।

• DAP आयात में यह उल्लेखनीय वृद्धि चीन द्वारा हाल ही में फॉस्फेट निर्यात में की गई कमी के बाद हुई है—एक रणनीतिक बदलाव जिसका वैश्विक उपलब्धता पर असर पड़ा है। सऊदी अरब के साथ यह नया समझौता भारत की गारंटीकृत आपूर्ति को बढ़ावा देता है, जिससे उसकी 10-11 मिलियन टन वार्षिक उर्वरक आवश्यकता के लिए अत्यंत आवश्यक आपूर्ति सुरक्षा मिलती है और एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम होती है।

Key Points:-

(i) सऊदी अरब से भारत का DAP आयात 2024-25 में 1.9 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है।

(ii) नए समझौते के साथ, कुल आयात मात्रा बढ़कर 3.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाएगी, जिससे राष्ट्रीय भंडार स्थिर हो जाएगा और सरकार की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) नीति को समर्थन मिलेगा।

(iii) इन समझौतों में भारत-विशिष्ट, अनुकूलित उर्वरकों पर संयुक्त अनुसंधान की योजनाएँ और पारस्परिक निवेश के नए रास्ते भी शामिल हैं—जिससे भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को सऊदी फॉस्फेट परियोजनाओं में निवेश करने और सऊदी निवेशकों को भारत के उर्वरक क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। भारत के उर्वरक सचिव और सऊदी के खनन उप-मंत्री के नेतृत्व में एक द्विपक्षीय कार्य समूह इन पहलों को आगे बढ़ाएगा।

2. WHO ने भारत के वैश्विक आयुष नेतृत्व को मान्यता देते हुए पहला AI-पारंपरिक चिकित्सा रोडमैप जारी किया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जुलाई 2025 में पारंपरिक चिकित्सा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के एकीकरण पर अपना पहला तकनीकी रोडमैप जारी किया। यह रिपोर्ट "पारंपरिक चिकित्सा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग का मानचित्रण" शीर्षक से जारी की गई, जिसमें आयुष (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) जैसी प्राचीन प्रणालियों के डिजिटलीकरण और वैश्वीकरण में भारत की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

- **भारत के प्रस्तावों के आधार पर विकसित यह रोडमैप, पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए एक वैश्विक AI-आधारित ढाँचे को औपचारिक रूप देने की दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला बड़ा कदम है। यह भविष्य के लिए साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा समाधान विकसित करने हेतु पारंपरिक चिकित्सा के साथ AI के संयोजन में भारत को अग्रणी स्थान पर रखता है।**

- **रोडमैप में भारत के प्लेटफार्मों जैसे कि SAHI (आयुर्वेदिक ऐतिहासिक छापों का प्रदर्शन), NAMASTE (राष्ट्रीय आयुष रुग्णता और मानकीकृत शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल), और ARP (आयुष अनुसंधान पोर्टल) को प्रमुख डिजिटल सक्षमकर्ता के रूप में महत्व दिया गया।**

- **इन प्लेटफार्मों का उद्देश्य सदियों पुराने चिकित्सा ग्रंथों को संरक्षित करना और दुनिया के लिए एक सुलभ शोध आधार प्रदान करना है। ARP पोर्टल दो महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाता है: पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना और विश्व स्तर पर स्वीकार्य AI-संवर्धित उपचार मॉडल तैयार करना।**

Key Points:-

(i) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने AI और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के नवाचार को स्वीकार करते हुए, इसे डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में एक अग्रणी शक्ति के रूप में मान्यता दी। इसने वैश्विक AI समुदायों और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साझेदारी में आयुष प्रणालियों के दस्तावेज़ीकरण, संहिताकरण और आधुनिकीकरण के भारत के प्रयासों की भी सराहना की।

(ii) भारत TKDL (पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी) स्थापित करने वाला पहला देश भी बन गया है, जिसने स्वदेशी चिकित्सा विरासत के ज़िम्मेदारीपूर्ण संरक्षण के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। TKDL अब AI-

समर्थित बुद्धिमत्ता और सुगमता के साथ पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के डिजिटलीकरण का एक वैश्विक मॉडल है।

3. अमेरिकी रक्षा विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा नवाचार के लिए OpenAI, गूगल, एंथ्रोपिक और xAI को 200 मिलियन डॉलर का AI अनुबंध प्रदान किया।

अमेरिकी रक्षा विभाग (DoD) ने हाल ही में OpenAI, गूगल, एंथ्रोपिक और xAI को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अनुबंध दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य रक्षा संचालन, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक निर्णय लेने सहित सुरक्षित और मिशन-संचालित AI अनुप्रयोगों के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली को मजबूत करना है।

• जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित ये अनुबंध, अमेरिकी जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन (GSA) और मुख्य डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिस (CDAO) द्वारा विकसित व्यापक AI अधिग्रहण रणनीति के अंतर्गत आते हैं।

• प्रत्येक कंपनी अमेरिकी संघीय एजेंसियों और सैन्य विभागों की सेवा के लिए उन्नत AI समाधान प्रदान करेगी, जैसे कि openAI का "चैटजीपीटी गॉव", गूगल का "जेमिनी AI", एंथ्रोपिक का "क्लाउड गॉव" और xAI का "ग्रोक फॉर गवर्नमेंट" मॉडल।

• OpenAI, जो अपने जनरेटिव AI टूल चैटजीपीटी के लिए जाना जाता है, को सुरक्षित युद्धक्षेत्र विश्लेषण और परिचालन तत्परता का समर्थन करने के लिए AI प्रोटोटाइप विकसित करने का काम सौंपा गया है। गूगल पब्लिक सेक्टर, अमेरिकी वायु सेना और नौसेना के साथ परियोजनाओं के लिए टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPUs) सहित उच्च-प्रदर्शन वाला बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, जो AI मॉडल प्रशिक्षण, सिमुलेशन और लॉजिस्टिक्स ऑटोमेशन पर केंद्रित होगा।

Key Points:-

(i) अमेज़न और गूगल द्वारा समर्थित एंथ्रोपिक, संवेदनशील रक्षा मिशनों में खतरे का पता लगाने, खुफिया प्रसंस्करण और नैतिक AI उपयोग में सुधार के लिए अपने क्लाउड गॉव मॉडल को तैनात करेगा।

(ii) इस बीच, एलन मस्क के नेतृत्व वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता फर्म xAI, वास्तविक समय के रणनीतिक तर्क और युद्धक्षेत्र AI अनुप्रयोगों को लक्षित करते हुए "सरकार के लिए ग्रोक" प्रदान करेगी।

(iii) रक्षा विभाग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये साझेदारियाँ सैन्य और असैन्य दोनों क्षेत्रों में AI को सुरक्षित और ज़िम्मेदारी से अपनाने में तेज़ी लाएँगी। रक्षा विभाग के मुख्य डिजिटल और AI अधिकारी डॉ. डग मैटी ने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय नैतिक और गोपनीयता मानकों का पालन करते हुए परिचालन श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए सुरक्षित AI परिनियोजन को आगे बढ़ाएगा।

4. IMF रिपोर्ट 2025: UPI द्वारा 18 बिलियन मासिक लेनदेन पार करने के साथ भारत वैश्विक फास्ट पेमेंट रैंकिंग में शीर्ष पर।

भारत तेज़ भुगतान में विश्व में अग्रणी बन गया है, और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) अब प्रति माह 18 अरब से ज़्यादा लेनदेन संसाधित कर रहा है। जुलाई 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के एक फिनटेक नोट के अनुसार, यह उछाल भारत के नकदी-रहित अर्थव्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ते कदम को दर्शाता है और डिजिटल लेनदेन की गति में एक वैश्विक मानक स्थापित करता है।

• भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा अप्रैल 2016 में शुरू किया गया UPI, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) प्लेटफ़ॉर्म पर चलता है। इसका इंटरऑपरेबल डिज़ाइन उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बैंकों और ऐप्स के साथ सहजता से लेनदेन करने की अनुमति देता है, जिससे यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रीयल-टाइम भुगतान सिस्टम बन जाता है।

Key Points:-

(i) जून 2025 में, UPI ने 18 अरब से ज़्यादा लेनदेन (सालाना आधार पर 32% की वृद्धि) और लेनदेन मूल्य में 20% की वृद्धि दर्ज की। दैनिक लेनदेन की संख्या लगभग 61.3 करोड़ तक पहुँच गई। इस बीच, नकदी उपयोग के प्रॉक्सी—जैसे ATM से निकासी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान—में लगातार गिरावट जारी रही।

(ii) "बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान: अंतर-संचालन का मूल्य" शीर्षक वाले IMF नोट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि कैसे UPI की खुली संरचना उपयोगकर्ता की पसंद, प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देती है। इसने अन्य देशों के लिए एक आदर्श के रूप में भी काम किया, अंतर-संचालन के महत्व पर प्रकाश डाला और नियामकों से संभावित बाज़ार संकेन्द्रण जोखिमों पर नज़र रखने का आग्रह किया।

(iii) रिपोर्ट में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में UPI की भूमिका को रेखांकित किया गया है, जिसके 50 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय उपयोगकर्ता हैं और भविष्य में सीमा-पार भुगतान, ऋण प्रवाह और UPI लाइट के ज़रिए फ़ीचर फ़ोन उपयोगकर्ताओं तक पहुँच बढ़ाने की इसकी क्षमता है। रिपोर्ट में UPI के खुले पारिस्थितिकी तंत्र और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए निरंतर नियामक सतर्कता की भी सिफ़ारिश की गई है।

5. भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 'टैलिसमैन सेबर 2025' में भाग लेगा।

जुलाई 2025 में, भारत ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 'टैलिसमैन सेबर 2025' के 11वें संस्करण में आधिकारिक रूप से शामिल हुआ, जो इस बड़े पैमाने के हिंद-प्रशांत रक्षा सहयोग में उसकी पहली भागीदारी को दर्शाता है। यह उपलब्धि भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों को मज़बूत करती है और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं सैन्य अंतर-संचालन को बढ़ावा देती है। यह अभ्यास 13

जुलाई से 4 अगस्त, 2025 तक ऑस्ट्रेलिया के कई स्थानों और पापुआ न्यू गिनी में विस्तारित अभियानों में आयोजित किया जा रहा है, जो क्षेत्रीय साझेदारी और बहुपक्षीय रक्षा समन्वय के विस्तार को दर्शाता है।

• टैलिस्मन सेबर सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2005 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य मित्र देशों के बीच सैन्य समन्वय, कमांड और नियंत्रण संरचनाओं, और रणनीतिक प्रतिक्रिया क्षमता को मज़बूत करना है। भारत की पहली भागीदारी 2025 में इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विकास बनाती है।

• 2025 के संस्करण में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम (यूके), जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, फिजी, थाईलैंड, सिंगापुर सहित 19 देशों के 35,000 से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं। मलेशिया और वियतनाम पर्यवेक्षक देशों के रूप में शामिल हैं।

• इस अभ्यास में लाइव-फायर एक्सरसाइज़, अम्पीबियस लैंडिंग, ग्राउंड ऑपरेशन, और एयर वॉरफेयर रणनीति शामिल हैं। सेना के बीच समन्वय और बहुपक्षीय रणनीति को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

Key Points:-

(i) भारत की भागीदारी में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रतिनिधि शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल (ADF) द्वारा UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल, HIMARS (हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम) और NASAMS (नेशनल एडवांस्ड सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम) जैसे उपकरणों का प्रदर्शन किया गया।

(ii) 'टैलिस्मन सेबर 2025' में भारत की भागीदारी इंडो-पैसिफिक में रक्षा कूटनीति को मज़बूत करती है और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे साझेदारों के साथ साझा सैन्य प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

(iii) पापुआ न्यू गिनी पहली बार इस अभ्यास की सह-मेजबानी कर रहा है। यह इंडो-पैसिफिक कमांड (INDOPACOM) क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक तैयारी और क्षेत्रीय रक्षा सहयोग को दर्शाता है।

BANKING & FINANCE

1. ताइवान का CTBC बैंक GIFT सिटी में शाखा खोलेगा, जिससे वैश्विक वित्तीय संबंध मजबूत होंगे।

जनवरी 2025 में, ताइवान के एक प्रमुख ऋणदाता, CTBC बैंक ने भारत के अग्रणी स्मार्ट और वित्तीय केंद्र, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) में अपनी पहली शाखा स्थापित करने के लिए ताइवान के वित्तीय पर्यवेक्षी आयोग (FSC) से अनुमोदन प्राप्त कर लिया। भारतीय अधिकारियों से अंतिम मंजूरी मिलने तक, यह कदम CTBC को GIFT सिटी के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में सीधे प्रवेश करने वाला पहला ताइवानी बैंक बना देगा।

• अप्रैल 2015 में शुरू किया गया और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के तहत संचालित, GIFT सिटी, भारत का प्रमुख ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और IFSC है जो गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। 886 एकड़ में फैले इस शहर में वर्तमान में 850 से अधिक वित्तीय और तकनीकी संस्थाएँ स्थित हैं, जिनमें 23 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बहुराष्ट्रीय

ऋणदाता और दो अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं।

• CTBC बैंक, GIFT सिटी में ताइवान की बढ़ती उपस्थिति में शामिल हो गया है, जिसमें ताइपे फूबोन कमर्शियल बैंक भी शामिल है, जिसे जुलाई 2025 में FSC अनुमोदन प्राप्त हुआ। भारतीय नियामक, नियामक संरेखण, कर लाभ और बाजार पहुंच को मजबूत चालकों के रूप में उद्धृत करते हुए, ताइवानी निवेश को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं।

Key Points:-

(i) GIFT सिटी स्पष्ट लाभ प्रदान करता है: एकल-खिड़की अनुमोदन, वैश्विक केंद्रों के साथ नियामक समानता, प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढाँचा, और अधिमान्य कर व्यवस्थाएँ। विदेशी बैंकों के लिए, यह व्यापार वित्त से लेकर ट्रेजरी और सीमा-पार संचालन तक, व्यापक सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक किफ़ायती मंच प्रदान करता है।

(ii) यदि यह चालू हो जाता है, तो CTBC बैंक नई दिल्ली और श्रीपेरंबदूर तथा ताइवान शाखाओं में अपने मौजूदा नेटवर्क का लाभ उठाकर भारतीय और ताइवान स्थित ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगा। GIFT सिटी में इसके विस्तार से उसे भारत के बढ़ते वित्तीय सेवा बाजार में प्रवेश करने और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

(iii) CTBC और ताइपे फूबोन जैसे वैश्विक बैंकों की बढ़ती संख्या के साथ, GIFT सिटी एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मज़बूत कर रहा है। IFSC का लक्ष्य नीतिगत प्रोत्साहनों और बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के माध्यम से और आगे बढ़ना है, और भारत को सिंगापुर और दुबई जैसे वैश्विक केंद्रों के लिए एक प्रतिस्पर्धी विकल्प के रूप में पेश करना है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा और गोवा के लिए नए राज्यपालों और कविंदर गुप्ता को लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया।

14 जुलाई, 2025 को, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा और गोवा राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए नए उपराज्यपाल (LG) की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी। ये नियुक्तियाँ संबंधित व्यक्तियों के पदभार ग्रहण करने के साथ ही प्रभावी हो जाएँगी।

• प्रोफेसर आशिम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लेंगे, जो जुलाई 2021 से इस पद पर कार्यरत थे। घोष अपने शैक्षणिक और राजनीतिक योगदान के लिए जाने जाते हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों में कई वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। वे पश्चिम बंगाल (WB) से हैं।

• पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, वे पी. एस. श्रीधरन पिल्लई का स्थान लेंगे। राजू आंध्र प्रदेश के एक वरिष्ठ राजनेता हैं और 2014 से 2018 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं।

• जम्मू-कश्मीर (J&K) के वरिष्ठ भाजपा नेता कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त

किया गया है। गुप्ता इससे पहले जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री (DCM) और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी.डी. मिश्रा का स्थान लेंगे, जो फरवरी 2023 से इस पद पर कार्यरत हैं।

Key Points:-

(i) लद्दाख के उपराज्यपाल पद से ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। भारतीय सेना के एक सम्मानित पूर्व सैनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के पूर्व कमांडर मिश्रा, लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त होने से पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे।

(ii) इन नियुक्तियों के साथ-साथ, राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1)(ए) के अंतर्गत चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। इन मनोनयनों में विधि, कूटनीति, सामाजिक कार्य और साहित्य के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो उच्च सदन में विविध प्रतिनिधित्व को रेखांकित करते हैं।

(iii) चार मनोनीत राज्यसभा सदस्य हैं: उज्ज्वल निकम, एक प्रसिद्ध सरकारी वकील जो 26/11 मुंबई हमलों और 1993 के विस्फोटों सहित हाई-प्रोफाइल आतंकवाद के मुकदमों में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं; हर्षवर्धन श्रृंगला, पूर्व भारतीय विदेश सचिव (जनवरी 2020 - अप्रैल 2022), और यूएसए और बांग्लादेश में पूर्व राजदूत; सी. सदानंदन मास्टर, केरल के एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् जो जमीनी स्तर के विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं; और डॉ. मीनाक्षी जैन, एक प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद जिन्हें भारतीय सभ्यता और इतिहास पर उनके साहित्यिक योगदान के लिए मान्यता प्राप्त है।

2. हेमंत रूपानी को सितंबर 2025 से हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज का नया CEO नियुक्त किया गया।

हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड (HCCB), भारत में कोका-कोला की सबसे बड़ी बॉटलिंग पार्टनर, ने हेमंत रूपानी को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है, जो 8 सितंबर, 2025 से कार्यभार संभालेंगे और निवर्तमान CEO जुआन पाब्लो रोड्रिग्ज का स्थान लेंगे।

- **हेमंत रूपानी को उपभोक्ता वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो दशकों से ज़्यादा का अनुभव है। जयपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से 1997 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय (FMS) से मार्केटिंग में MBA करने के बाद, उन्होंने ICI इंडिया लिमिटेड में अपना करियर शुरू किया, फिर 2016 में मोंडेलेज़ इंटरनेशनल में जाने से पहले पेप्सिको, इंफोसिस टेक्नोलॉजीज, वोडाफोन और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाईं।**

- **HCCB में शामिल होने से पहले, रूपाणी मोंडेलेज़ इंटरनेशनल में दक्षिण पूर्व एशिया (SEA) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड सहित कई देशों में व्यावसायिक संचालन की देखरेख करते थे। उन्होंने भारत में बिक्री का नेतृत्व करने से**

लेकर कई बाजारों का प्रबंधन करने तक का सफर तय किया, जो उनके नौ साल के परिवर्तनकारी कार्यकाल को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) हेमंत रूपानी, जुआन पाब्लो रोड्रिग्ज का स्थान लेंगे, जिन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक HCCB का नेतृत्व किया और फिलीपींस, मैक्सिको, सिंगापुर और भारत जैसे बाजारों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। रोड्रिग्ज कोका-कोला प्रणाली में एक नए पद पर नियुक्त होंगे, क्योंकि HCCB दिसंबर 2024 में जुबिलेंट भारतीय समूह द्वारा 40% हिस्सेदारी अधिग्रहण (लगभग ₹12,500 करोड़) के बाद स्थानीय स्वामित्व को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

(ii) बेंगलुरु में मुख्यालय और 1997 में स्थापित, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज़ 7,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के साथ काम करता है और भारत में कोका-कोला उत्पादों के प्रमुख बोतल निर्माता और वितरक के रूप में कार्य करता है। रूपाणी के नेतृत्व में, एचसीसीबी का लक्ष्य निवेश-आधारित विकास को गति देना, अपने ₹12,500 करोड़ के संयुक्त उद्यम की दक्षता में वृद्धि करना और भारत में अपनी मज़बूत बाज़ार स्थिति का लाभ उठाना है।

3. आर.डी.डोरईस्वामी को 2028 तक LIC का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया।

जुलाई 2025 में, रामचंद्रन दोरैस्वामी आधिकारिक तौर पर भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पदभार ग्रहण करेंगे। उनका तीन वर्षीय कार्यकाल (या 62 वर्ष की आयु तक) अगस्त 2028 में समाप्त होगा, जो भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है।

- **वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) ने चार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के बाद, 11 जून, 2025 को दोरईस्वामी को इस शीर्ष पद के लिए अनुशंसित किया। इसके बाद, उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा अनुमोदित किया गया और वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया।**

Key Points:-

(i) दोरईस्वामी ने सतपाल भानु का स्थान लिया, जो 7 जून को सिद्धार्थ मोहंती की सेवानिवृत्ति के बाद 8 जून, 2025 से अंतरिम MD और CEO के रूप में कार्यरत थे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त, 2028 तक या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक रहेगा।

(ii) मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से गणित स्नातक, दोरईस्वामी भारतीय बीमा संस्थान के फेलो हैं और उन्हें संचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक क्षेत्रों में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने चेन्नई, कोट्टायम और पुणे में कार्यकारी निदेशक (IT)

और क्षेत्रीय विपणन प्रमुख जैसे पदों पर कार्य किया है।

(iii) MD और CEO के रूप में, दोरईस्वामी IPO के बाद के दौर में LIC के बदलाव का नेतृत्व करेंगे और ₹45 लाख करोड़ की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (AUM), डिजिटल नवाचार, उत्पाद विस्तार और निवेशक विश्वास पर नज़र रखेंगे। उनके नेतृत्व पर हितधारकों और बाज़ार विश्लेषकों दोनों की नज़र है।

AWARDS

1. लीला अबूलेला ने प्रवासन और मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर अपने सशक्त साहित्यिक कार्य के लिए 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार जीता।

जुलाई 2025 में, प्रसिद्ध सूडानी-स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला को अंग्रेजी पेन द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान, विशेष रूप से प्रवासन, इस्लामी आस्था और प्रवासी व विस्थापन में मुस्लिम महिलाओं के अनुभवों जैसे विषयों पर उनके गहन लेखन के लिए दिया जाता है।

• पेन पिंटर पुरस्कार इंग्लिश पेन द्वारा प्रतिवर्ष उस लेखक को प्रदान किया जाता है जो निडरता से सत्य, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के विषयों पर लेखन करता है। 2025 के संस्करण की घोषणा लंदन, यूनाइटेड किंगडम (यूके) स्थित अक्टूबर गैलरी में इंग्लिश पेन समर पार्टी के दौरान की गई, जो इस साहित्यिक सम्मान के 16वें वर्ष का प्रतीक है।

• लीला अबूलेला को 10 अक्टूबर, 2025 को लंदन स्थित ब्रिटिश लाइब्रेरी (BL) में एक समारोह के दौरान औपचारिक रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान, अबूलेला और इंग्लिश पेन द्वारा संयुक्त रूप से चुने गए पेन पिंटर राइटर ऑफ़ करेज 2025 के सह-विजेता की भी घोषणा की जाएगी - जो विश्व स्तर पर उत्पीड़ित या खामोश की गई आवाज़ों को उजागर करेगा।

Key Points:-

(i) 2025 के चयन पैनल में इंग्लिश पेन की अध्यक्ष रूथ बोर्थविक, कवि और लेखिका मोना अर्शी और प्रख्यात उपन्यासकार नादिफा मोहम्मद जैसी साहित्यिक हस्तियाँ शामिल थीं। निर्णायकों ने अबुलेला की व्यक्तिगत कहानियों को वैश्विक सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं से जोड़ते हुए, निर्वासन में मुस्लिम महिलाओं के संघर्षों और ताकत की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करने वाली कहानियाँ गढ़ने की क्षमता की प्रशंसा की।

(ii) नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पिंटर के सम्मान में 2009 में स्थापित पेन पिंटर पुरस्कार, अंग्रेजी में निडरता से सत्य कहने के लिए UK, आयरलैंड या राष्ट्रमंडल के किसी 'साहसी लेखक' को सम्मानित करता है।

(iii) लीला अबुलेला छह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित उपन्यासों की लेखिका हैं, जिनमें द ट्रांसलेटर (1999), मिनारेट (2005), लिरिक्स एले (2011), और उनकी नवीनतम पुस्तक रिवर स्पिरिट (2023) शामिल हैं। उन्होंने अपनी लघु कहानी "द म्यूज़ियम" के लिए 2000 में अफ्रीकी लेखन के लिए केन पुरस्कार और "लिरिक्स एले" के लिए स्कॉटिश बुक अवार्ड जीता। उनकी रचनाएँ BBC रेडियो 4 लघु

कथा पुरस्कारों में अक्सर प्रदर्शित होती रही हैं, और उन्हें 2018 में साल्टायर फिक्शन बुक ऑफ़ द ईयर के लिए चुना गया था।

2. पूर्व मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 से सम्मानित किया गया।

जुलाई 2025 में, पूर्व मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को काठमांडू में प्रतिष्ठित हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 से सम्मानित किया गया। ₹200,000 की राशि के साथ दिए जाने वाले इस पुरस्कार ने न्यायिक नेतृत्व, संस्थागत विकास, और संक्रमणकालीन न्याय एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में उनके असाधारण योगदान को मान्यता दी।

- **यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नमक व्यापार निगम के संस्थापक हेम बहादुर मल्ला के नाम पर रखा गया है और इसे नेपाल लोक प्रशासन संघ (NPAA) द्वारा 2003 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।**
- **2025 में मुख्य न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ने एनपीएए और निगम के एक संयुक्त कार्यक्रम के दौरान श्रेष्ठ को यह सम्मान प्रदान किया।**

Key Points:-

(i) नेपाल के 25वें मुख्य न्यायाधीश, श्री श्रेष्ठ को कानूनी सुधार, समावेशी लोकतंत्र और पर्यावरणीय न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा मिली। उनके कार्यकाल में नेपाल के संघर्षोत्तर संवैधानिक परिवर्तन और व्यापक शांति समझौते के दौरान महत्वपूर्ण न्यायिक सक्रियता शामिल थी।

(ii) पूर्व लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति ने श्रेष्ठ को उनके नेतृत्व और संस्थागत सुदृढ़ीकरण प्रयासों के लिए अनुशंसित किया। इस पुरस्कार में NPR200,000 (लगभग ₹200,000) का नकद पुरस्कार और एक सम्मान पत्र शामिल है।

(iii) यह पुरस्कार सुशासन, न्यायिक स्वतंत्रता और उत्कृष्ट लोक सेवा को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को मान्यता देने के प्रति नेपाल के समर्पण को दर्शाता है। मुख्य न्यायाधीश राउत ने श्रेष्ठ की नेपाल के कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में प्रशंसा की।

IMPORTANT DAYS

1. लड़कियों के शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए 12 जुलाई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2025 मनाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2025 को 12 जुलाई 2025 को दुनिया भर में मनाया गया। यह दिन मलाला यूसुफजई की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की पाकिस्तानी शिक्षा कार्यकर्ता हैं। यह

दिवस विश्व समुदाय द्वारा हर लड़की को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

• यह दिन बालिकाओं की शिक्षा और उनके समान शैक्षणिक अवसरों के लिए चल रहे वैश्विक संघर्ष को रेखांकित करता है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में आने वाली चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है और मलाला जैसी कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है, जो शैक्षिक न्याय की वैश्विक प्रतीक बन चुकी हैं।

• इस दिन की शुरुआत 12 जुलाई 2013 को तब हुई जब मलाला ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र (United Nations) मुख्यालय में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा के अधिकार पर बल दिया। यह भाषण 2012 में तालिबान के हमले से बचने के बाद उनका पहला बड़ा वैश्विक मंच था। इसी भाषण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक युवा नेता के रूप में स्थापित किया।

• इस भाषण के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से 12 जुलाई को "मलाला दिवस" घोषित किया। इस दिन को पहली बार अंतरराष्ट्रीय रूप से 12 जुलाई 2013 को मनाया गया। इसके बाद से यह हर साल मनाया जाता है ताकि दुनिया को यह याद दिलाया जा सके कि शिक्षा के अधिकार की लड़ाई अभी अधूरी है।

Key Points:-

(i) मलाला दिवस 2025 का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासचिव की "Global Education First Initiative" (GEFI – वैश्विक शिक्षा प्रथम पहल) का भी समर्थन करता है। यह पहल 2012 में शुरू हुई थी, जो दुनियाभर की सरकारों और समाज को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है, खासकर बालिकाओं के लिए।

(ii) मलाला यूसुफजई, जिनका जन्म 1997 में पाकिस्तान की स्वात घाटी में हुआ था, 2012 में एक लक्षित हमले में बचने के बाद एक वैश्विक आइकन बन गईं।

(iii) बाद में उन्होंने अपने संस्मरण "I Am Malala" का सह-लेखन किया और 2014 में 17 वर्ष की आयु में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनीं। उनकी संस्था, मलाला फंड, सभी लड़कियों के लिए 12 साल की मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में काम करती है।

2. विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2025 को मनाया गया।

15 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस 2025, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित इस दिवस की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस वर्ष का विषय—'कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण'—युवाओं को रोज़गार, उद्यमिता और सतत विकास के लिए भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं से लैस करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

• नवंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा स्थापित विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था। तब से, यह वैश्विक कौशल अंतर को पाटने के लिए सरकारों, शिक्षकों,

उद्योग और युवाओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

• 2025 का विषय तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (TVET) प्रणालियों में AI और डिजिटल कौशल के एकीकरण पर ज़ोर देता है। ये कौशल बुनियादी डिजिटल साक्षरता से लेकर उन्नत डेटा विज्ञान, कोडिंग, VR/AR और साइबर सुरक्षा तक हैं—जो समावेशी, तकनीक-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Key Points:-

(i) UNESCO-UNEVOC जैसे संगठनों ने पेरिस में वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी की, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश (UP) ने राष्ट्रीय मेलों और नवाचार मंचों का शुभारंभ किया। यूपी के स्किल ओलंपिक में AI, ड्रोन तकनीक, स्वास्थ्य-तकनीक और कृषि-तकनीक में युवाओं के नवाचारों का प्रदर्शन किया गया; बिहार ने डिजिटल कला और एआई जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

(ii) यह दिवस सतत विकास लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), सतत विकास लक्ष्य 8 (सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास), और सतत विकास लक्ष्य 10 (असमानताओं में कमी) के अनुरूप है। AI-समावेशी कौशल की वकालत करके, इस दिवस का उद्देश्य लाखों युवाओं के लिए शिक्षा और सार्थक रोज़गार तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है।

DEFENCE

1. भारतीय सेना ने अत्याधुनिक युद्ध तकनीकों को उजागर करने के लिए मेरठ में 'प्रचंड शक्ति' का प्रदर्शन किया।

जुलाई 2025 में, भारतीय सेना के राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में खड़गा कोर फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में अपनी क्रांतिकारी "प्रचंड शक्ति" का प्रदर्शन किया।

• लाइव अभ्यास ने स्ट्राइक कोर के पैदल सेना संचालन के भीतर उन्नत प्रौद्योगिकियों - जैसे ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लोइटरिंग म्यूनिशन और स्वायत्त प्रणालियों - के एकीकरण को रेखांकित किया।

• इस अभ्यास में युद्धक्षेत्र आधुनिकीकरण के प्रति सेना की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया - जिसमें मानव रहित हवाई वाहन (UAVs), AI-सक्षम प्लेटफॉर्म, लोइटरिंग म्यूनिशन और स्वायत्त हथियार प्रणालियों की तैनाती शामिल है - ताकि गहन आक्रामक मिशनों के दौरान पैदल सेना की संरचनाओं की चपलता, मारक क्षमता और उत्तरजीविता को बढ़ाया जा सके।

Key Points:-

(i) प्रचंड शक्ति व्यापक "टेक अवशोषण वर्ष" अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया नवाचारों और नागरिक-विकसित सैन्य समाधानों के एकीकरण में तेजी लाना है, जिससे सेना की आत्मनिर्भरता और भविष्य की तैयारी को बल मिलेगा।

(ii) खरगा कोर के राम डिवीजन के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में वरिष्ठ नेतृत्व ने भाग लिया और स्ट्राइक

कोर परिदृश्यों में ड्रोन झुंडों, AI-संचालित लक्ष्यीकरण और सटीक लोइटरिंग हथियारों के वास्तविक समय के अनुप्रयोग पर प्रकाश डाला गया - जो परिचालन सिद्धांत में एक बड़े बदलाव का संकेत था।

(iii) वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के अनुसार, प्रचंड शक्ति डिजिटल, नेटवर्कयुक्त युद्ध की ओर एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। यह अभ्यास पैदल सेना इकाइयों को भविष्य के युद्ध उपकरणों से सुसज्जित करता है, जिससे उच्च-तीव्रता वाले अभियानों में त्वरित अनुकूलनशीलता सुनिश्चित होती है और भारत के रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूती मिलती है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. DRDO और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा में सुखोई-30 MKI से स्वदेशी अस्त्र BVRAAM मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया।

जुलाई 2025 में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय वायु सेना (IAF) ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर से लैस, स्वदेशी रूप से विकसित अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) का Su-30 MKI विमान से सफल उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) में किया गया।

• इस परीक्षण में दो अस्त्र मिसाइलों को अलग-अलग युद्ध स्थितियों में प्रक्षेपित किया गया। दोनों मिसाइलों ने अपने निर्धारित हवाई लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया। परीक्षणों से DRDO द्वारा विकसित मिसाइल के सीकर प्रदर्शन की पुष्टि हुई, जो सभी मानकों पर सफलतापूर्वक खरा उतरा।

• यह परीक्षण भारत के रक्षा स्वदेशीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। RF सीकर, जो आधुनिक मिसाइल मार्गदर्शन का एक प्रमुख घटक है, दागो और भूल जाओ क्षमता के साथ स्वायत्त लक्ष्य ट्रैकिंग और भेदन की अनुमति देता है। इसने अस्त्र को अपनी श्रेणी की सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक बना दिया है।

• अस्त्र मिसाइल प्रणाली का परीक्षण ITR चांदीपुर द्वारा तैनात उच्च-परिशुद्धता टेलीमेट्री प्रणालियों का उपयोग करके किया गया। आँकड़ों ने उड़ान के दौरान सीकर और मार्गदर्शन तंत्रों के त्रुटिरहित संचालन की पुष्टि की, जो उच्च-स्तरीय रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) अस्त्र BVRAAM को DRDO द्वारा विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा निर्मित किया गया है। इसकी उच्च गति सीमा 100 किमी तक है, इसमें मध्य-शरीर वाला विंग विन्यास है, और इसका भार 160-180 किलोग्राम है।

(ii) यह मिसाइल अत्यधिक फुर्तीले दुश्मन विमानों और मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) को निष्क्रिय करने में सक्षम है। वर्तमान परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमान का उपयोग करके किए गए थे, और भविष्य में तेजस MK-1, MiG-29K और भारतीय नौसेना के लड़ाकू बेड़े जैसे प्लेटफार्मों पर इसके एकीकरण की योजना है।

Static GK

Indian Institute of Corporate Affairs(IICA)	महानिदेशक (DG) CEO : ज्ञानेश्वर कुमार	मुख्यालय : गुरुग्राम, हरियाणा
Saudi Arabia	राजधानी: रियाद	मुद्रा: सऊदी रियाल
WHO	महानिदेशक: डॉ. टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस	मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
Google	CEO : सुंदर पिचाई	मुख्यालय: माउंटेन व्यू, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
International Monetary Fund (IMF)	प्रबंध निदेशक (MD) : क्रिस्टालिना जॉर्जीवा	मुख्यालय : वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
Australia	प्रधानमंत्री (PM) : एंथनी अल्बानीज़	राजधानी : कैनबरा
Indian Army (IA)	थल सेनाध्यक्ष (COAS): जनरल उपेंद्र द्विवेदी	मुख्यालय: नई दिल्ली
Haryana	मुख्यमंत्री: नायब सिंह सैनी	राज्यपाल: अशीम कुमार घोष
DRDO	अध्यक्ष: समीर वी. कामत	मुख्यालय: नई दिल्ली
Ministry of Communications (MoC)	मंत्री: ज्योतिरादित्य सिंधिया	मुख्यालय: नई दिल्ली
LIC	स्थापना: 1956	मुख्यालय: मुंबई